



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव अन्त्योदय कल्याण समारोह

मुख्य अतिथि
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

27 मार्च, 2025 | अपराह्न 12:00 बजे | पुलिस परेड ग्राउंड, भरतपुर

हस्तांतरण / वितरण / शुभारम्भ

- 92 हजार निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण
- डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय योजना हेतु 300 करोड़ रुपए
- दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर एवं असिस्टिव डिवाइस
- 20 हजार परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना में पट्टा वितरण
- माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरण
- ग्रामीण विकास का नया ई-वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल एप

योजनाओं के दिशा निर्देश

- पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना
- दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना
- दिव्यांगजनों हेतु समान अवसर नीति का विमोचन
- गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना
- एमएलए लैड योजना के तहत विधायक जन सुनवाई केंद्र
- पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली में 150 यूनिट मुफ्त बिजली
- MAA योजना के तहत न्यू पैकेज एवं मा नेत्र वाउचर योजना

पुलिस के 150 नए वाहनों की रवानगी

27 मार्च, 2025 | जवाहर सर्किल, जयपुर

अन्त्योदय कल्याण - खुशहाल राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

'किसान सिर्फ खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं'

मु.मंत्री भजनलाल ने बीकानेर में आयोजित किसान सम्मेलन को किसानों के सम्मान को समर्पित बताया

मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर जोर दिया और इसके लिए तीस हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

किसान सम्मेलन एवं एफ.पी.ओ. कार्यक्रम में तीस हज़ार किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान हस्तांतरित किया गया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 30 हज़ार किसानों को 137 करोड़ रुपये का अनुदान, हस्तांतरण किया।

चुड़ें, जिससे वे लाभ की खेती कर खुद को सशक्त बना सकें। शर्मा बुधवार को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा, किसान सिर्फ

खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं। आज बीकानेर में हुए किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम में 30 हज़ार किसानों को 137 करोड़ रुपये का अनुदान, हस्तांतरण किया गया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती किये जाने पर 30 हज़ार रु. की प्रोत्साहन राशि के दिशा-निर्देश जारी किए गए। पीएमएफएमई योजना के

तीन एफपीओ को अनुदान के तथा एक एफपीओ को शेयर मनी के बैंक वितरण किए गए। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 10 हज़ार एफ.पी.ओ. का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 72 लाख से अधिक किसानों को 1 हज़ार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण, लगभग 47

लाख किसानों को 29 हज़ार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि उन्होंने खेती का हर काम किया है तथा वे किसानों की समस्या को भलीभांति समझते हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'गहलोत सिर्फ टिक्टर पर ही एक्टिव रहते हैं'

बीकानेर, 26 मार्च (कास)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिक्टर पर सक्रियता व पूर्व वार्डों को लेकर गहलोत पर जमकर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री टिक्टर पर सक्रिय रहते हैं लेकिन विधानसभा में एक दिन भी नहीं आये। वे दिनभर टिक्टर पर चलते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री बीकानेर की एपीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा- सिर्फ सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने किसान सम्मेलन में कहा, गहलोत एक बर्ष भी विधानसभा में नहीं आए।

पर सक्रिय रहने से जनता के दुख-दर्द कम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत टिक्टर पर रहने से पहले अपने पांच साल की सरकार के कामों को देख लें।

इस पर गहलोत ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि आज मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायत बताने वाले और सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे टिक्टर पर टिप्पणी की है।

मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग ढाई साल पुराना आपका टिक्टर याद दिलाता चाहता हूँ, जिसमें आपने कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएलपी पर खरीद की मांग की थी और विरोध जताया था।

अमेरिका से आयातित सामान पर भारत, टैरिफ आधा करने को तैयार

इस टैरिफ में कमी से 23 अरब डॉलर का नुकसान होगा भारत को, पर, भारत से अमेरिका को निर्यात, जिसकी कीमत 66 अरब डॉलर आंकी जाती है, सुरक्षित रहने की आशा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 मार्च। अमेरिका के रिसिप्रोकल टैरिफ (जो जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएगा) जो 2 अप्रैल 2025

66 अरब डॉलर के निर्यात को रिसिप्रोकल टैरिफ की मार से बचना है। लेकिन प्रस्तावित कटौती इस बात पर निर्भर है कि अमेरिका अपने सुनियोजित करों से कितनी राहत देता है। प्रमुख उद्योगों जैसे फार्मास्युटिकल्स और

सबसे पहले भारत, इलैक्ट्रिक वाहनों की बैट्री के निर्माण में आवश्यक सामान पर टैरिफ बहुत कम करना चाहता है, जिससे स्थानीय उद्योगपतियों व निर्माताओं का माल विदेशों में मार्केट किया जा सके।

सरकार द्वारा किये गये आंकलन के अनुसार, भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट का 87 प्रतिशत हिस्सा, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ से प्रभावित होगा। अतः भारत सरकार अमेरिका से आयातित माल पर टैरिफ में 5 से 30 प्रतिशत की कमी कर सकती है।

से लागू होने जा रहा है, के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार आधे से ज्यादा अमेरिकन आयात पर टैरिफ घटाने का विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका को हो रहे भारत के

ऑटो मोबाइल्स को इस समय काफी खतरा है, हालांकि कुछ कृषि उत्पादों की कटौती से राहत दी जा सकती है। यह कदम अगले सप्ताह से लागू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुँची पुलिस

स्टोर रूम व आसपास की जगह सील कर दी गई है

नई दिल्ली, 26 मार्च। दिल्ली पुलिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुँचकर उनके स्टोर रूम और आसपास की जगह सील कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचे। आग लगने वाली जगह को जांच कमेटी के कहने पर सील किया है। दिल्ली पुलिस ने स्टोर रूम और आसपास की जगह का दौरा किया।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले में लगी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस संजिव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील मैथ्यूज जे नेदुम्वरा ने आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि यह व्यापक जनहित

सुप्रीम कोर्ट की जाँच कमेटी के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने यह कार्यवाही की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया।

से संबंधित है। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन एफआईआर की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा, सार्वजनिक बयान न दें।

मामले में एक महिला और सह-याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर ऐसा मामला किसी आम नागरिक के खिलाफ

होता तो सीबीआई और ईडी जैसी कई जांच एजेंसियां उसके पीछे लग जातीं। सीजेआई ने कहा, यह काफी है। याचिका पर उसी के अनुसार सुनवाई होगी। नेदुम्वरा और तीन अन्य लोगों ने रविवार को एक याचिका दायर कर पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।

कथित नकदी की बरामदगी 14 मार्च को रात करीब 11.35 बजे जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद हुई। मौके पर अग्निशमन अधिकारी पहुंचे थे। विवाद के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय के कोलॉजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने की सिफारिश की। 22 मार्च को सीजेआई ने आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया और घटना में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की जांच रिपोर्ट अपलोड करने का फैसला किया।

पेपर लीक केस, तृतीय श्रेणी अध्यापक राजेन्द्र यादव सस्पेंड

जयपुर, 26 मार्च। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक करने के मामले में तृतीय श्रेणी अध्यापक को शिक्षा विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरोपी जय शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय उच्च माध्यमिक खतीपुरा में तैनात था, तब उसने पेपर आउट किया था। आरोपी जगदीश

आरोपी जगदीश विश्वादेव गैंग का सदस्य था तथा कई परीक्षाओं के पेपर लीक में लिप्त था।

विश्वनाई गैंग का सक्रिय सदस्य है। एसओजी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी और अभी वह न्यायिक अभिरक्षा में है। राजेन्द्र कुमार यादव मेजर दिग्विजय सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खतीपुरा, जयपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। पंकज चौधरी उर्फ यूनिवर्सिटी जयपुर जगदीश विश्वादेव के साथ संगठित गिरोह में शामिल होकर राजेन्द्र यादव प्रतियोगी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायालय कुछ भी कहते रहें, 'बुलडोजर न्याय' का चलन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा

राजनीतिक नेतृत्व को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं लगती कि सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर जस्टिस के बारे में क्या गाइडलाइन्स हैं

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने चार महीने पहले "न्याय से परे के ध्वस्तीकरण (एक्स्ट्रा-जुडिशियल डिमांड्स) को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, तथा म्यूनिसिपल अधिकारियों के लिये गाइडलाइन जारी कर दी थीं, जिन्हें भवन गिराने की कार्यवाही करने से पहले ध्यान में रखना अनिवार्य था, इसके बावजूद, "बुलडोजर जस्टिस" यथावत एवं अक्षुण्ण रूप से जारी है। पिछले सोमवार को, नागपुर म्यूनिसिपल अधिकारियों ने फहीम खान नामक व्यक्ति के घर के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से ढहा दिया। यह व्यक्ति 17 मार्च को शहर में हुये दंगों का आरोपी है। इस घटना के कुछ घंटे बाद, बम्बई उच्च न्यायालय ने मकान गिराये जाने पर स्टे दे दिया तथा उस क्षेत्र के अन्य मकानों को ध्वस्त करने प्रक्रिया रोकने के आदेश जारी कर दिये। इससे

उत्तर प्रदेश के मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ ने "बुलडोजर जस्टिस" के पक्ष में कहा, "कुछ लोगों के लिए जरूरी होता है, उनको उसी भाषा में बताया जाए, जो वे समझते हैं।"

पहले 23 फरवरी को, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक मकान ढहा दिया गया था। इस घटना को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान "भारत-विरोधी नारे" लगाये जाने के दण्ड के रूप में देखा गया था। किताबुल्ला-हमीदुल्ला ने सर्वोच्च न्यायालय पहुँच कर, अदालत के 13 नवम्बर के आदेश की मानहानि का आरोप लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में सोमवार को नोटिस जारी करके, सम्बंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

"हयूमन राइट्स ग्रुप एनिस्टी इन्टरनेशनल" के अनुसार, आप-शासित पंजाब के अलावा, चार भाजपा-शासित राज्यों में, सर्वोच्च न्यायालय

कमिश्नर के समक्ष पेश की जायेगी तथा उसे सार्वजनिक किया जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये गाइडलाइन सडक, फुटपाथ या जल-भंडारण तंत्रों, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बने अनधिकृत मकानों के मामले में लागू नहीं होंगी। अदालत द्वारा आदेशित ध्वस्तीकरण के मामलों में भी ये गाइडलाइन लागू नहीं होंगी। लेकिन जैसा इस मामले में हुआ है, राज्य सरकारें बुलडोजर कार्यवाही करने में इन्हीं छूटों का सहारा ले रही हैं।

ध्वस्तीकरण निषेध की सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन्स को लेकर राजनेताओं का चिन्तित होना अनावश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। "बुलडोजर कार्यवाही" के बचाव में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि "कुछ लोगों से निबटने के लिये उसी तरीके की जरूरत होती है, जिसे वे समझते हैं।..... (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में चार नए जज नियुक्त

जयपुर, 26 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट को चार नए न्यायाधीश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम की ओर से गत दिनों आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह के नामों की भेजी सिफारिश को केन्द्र सरकार ने मान लिया है। वहीं, राष्ट्रपति भवन से इनके नियुक्ति वारंट भी जारी

सुप्रीम कोर्ट कोलॉजियम ने चार जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसे केन्द्र सरकार ने मान लिया है।

कर दिए गये हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ, जोधपुर में जल्दी ही इनकी और से शपथ ली जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में फिलहाल 34 न्यायाधीश नियुक्त हैं। वहीं, इन चारों के शपथ लेने के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी, हालांकि हाईकोर्ट में जजों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सदा से वित्तीय संयम का पाठ पढ़ाने वाले अमीर देशों की इस मुद्दे पर हालत काफी चिंताजनक है

ये तथाकथित अमीर देश, अपने ऋणों पर जो ब्याज दे रहे हैं, वो उनके रक्षा बजट से भी ज्यादा है

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मार्च। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओ.ई.सी.डी.) ने 2025 के लिए अपनी वैश्विक कर्ज सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जो विकास और आय के स्पेक्ट्रम में देशों की कुल कर्ज की स्थिति को लेकर एक गंभीर तस्वीर पेश करती है।

इसमें कई सच्चाइयाँ सामने आई हैं, जिनमें उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो पारंपरिक रूप से इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सरकार का खर्च सीमा में हो और ऋणभार ज्यादा बड़े।

ओ.ई.सी.डी., जिसे समृद्ध देशों का क्लब कहा जाता है, ने यह खुलासा किया है कि यूरोप के अत्यधिक विकसित देश अपने बकाया कर्जों का भुगतान करने के लिए अपने वार्षिक रक्षा

यह भी एक कारण है कि वे रूस के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि, जैसा कि ट्रंप की शिकायत है, इन देशों की आदत पड़ गई है कि उनकी सुरक्षा का आर्थिक भार तो अमेरिका वहन कर ही लेगा। अतः, उनकी सेना की स्थिति काफी कमजोर है, रूस की तुलना में।

ये सभी तथ्य, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओ.ई.सी.डी.) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में लिखे हैं।

उन्नत देशों का अन्तरराष्ट्रीय ऋण 17 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, 2025 में, जबकि 2023 में यह ऋण 14 ट्रिलियन डॉलर ही था। दूसरी ओर विकासशील देशों का ऋण 2024 में कुल तीन ट्रिलियन डॉलर ही था।

पर, यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के ऋण कभी अदा नहीं होते तथा पुराने ऋण की सर्विस के लिये नये ऋण ले लिये जाते हैं, कुछ और बढ़ी हुई ब्याज दर पर।

और, इस प्रकार ऋण पर ब्याज का भार बढ़ता ही रहता है। परन्तु, भारत के ऋण की स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, अब तक।

बजट से अधिक खर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह उस बात को रेखांकित करता है, जो अमेरिकियों ने बहुत कठोर शब्दों में उनसे कही थी कि ये देश खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त खर्च नहीं कर पा रहे हैं और अमेरिका पर जिम्मेवारी ढाल रहे हैं कि वो दुश्मन के आक्रमणों

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा को जान से मारने की धमकी

जयपुर, 26 मार्च। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को बुधवार देर शाम को जयपुर सेंट्रल जेल से जान से मारने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी में सामने आया है कि एक बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बैरवा

पता चला है कि जयपुर सेंट्रल जेल से किसी बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर धमकी दी।

को मारने की धमकी दी है। इसके बाद, जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम तैनात ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की सूचना पुलिस के आलाधिकारी को दी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम इंचार्ज से जिस नंबर से फोन आया, उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। मोबाइल की लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल आई। पूर्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देश के वीर शहीदों के सम्मान में सभी को आगे आना चाहिए : दीया कुमारी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शहीद हवलदार रामजीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया

खिरोड़, (निर्स)। कस्बे के राजस्व गांव कैमरी ढाणी के शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा के 22वें शहादत दिवस पर शहीद की प्रतिमा अनावरण उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुष्प चक्र अर्पित करके किया। वहीं अनावरण पट्टिका का लोकार्पण भी किया गया।

नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल के अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के विशेष अतिथि नवलगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेंद्र सेनी, खिरोड़ ग्राम पंचायत के सरपंच महावीर प्रसाद भामू व पंचायत समिति सदस्य जानकी देवी थे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शेखावाटी की वीर शहीदों की भूमि बताते हुए कहा कि देश के इन वीर शहीदों के सम्मान में सभी को आगे आना चाहिए और देश के शहीदों एवं उनके परिवारों का सम्मान करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रयास करते हुए कारगिल में शहीद हुए जवानों की पार्थिव देह उनके घरों तक पहुंचाई गई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहीदों के परिवारों के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न तरह से भागीदारी निभाई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी



कैमरी ढाणी वासियों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का हल भेंट करके सम्मान किया।

ने हाल ही में बजट में नवलगढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में बताया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के लिए बहुत सी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है और देश की जनता को भी डबल इंजन की सरकार पर विकास कार्यों को लेकर विश्वास है। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खिरोड़ क्षेत्र के लोगों के लिए खिरोड़ के राजस्व गांव तुरकानी जोहड़ी से लेकर राजस्व गांव कैमरी ढाणी तक 5 किलोमीटर

की सड़क शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा के नाम से बनाने की घोषणा करते हुए सड़क की सीमा तय की है। कार्यक्रम को नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल ने संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार हमेशा विकास के लिए तत्पर रहती है। वहीं शहीदों के सम्मान के लिए भी हर समय तैयार रहती है। युवाओं को चाहिए कि वे अपने बुजुर्ग सैनिकों से प्रेरणा लेते हुए देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहें। देश में जाति लाने के लिए युवाओं को आगे आना

चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंडेला विधायक सुभाष मौल ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शेखावाटी के कण-कण में शहीदों का नाम है। शहीद हमेशा अमर रहते हैं और देवताओं के समान माने जाते हैं। इसलिए शहीदों का देवताओं की तरह ही पूजन करना चाहिए। इससे पूर्व कैमरी ढाणी वासियों द्वारा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को हल भेंट करके सम्मान किया गया। वहीं शहीद रामजीलाल कटेवा के परिवार की ओर

से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का चुनौती ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद रामजीलाल कटेवा की वीरगाथा प्रभाती देवी सहित पूरे परिवार का शॉल ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिह्न भेंट करके सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह शेखावत का प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मान किया गया। खिरोड़ सरपंच महावीरप्रसाद भामू एवं कार्यक्रम के आयोजन रिटायर्ड सुबेदार मेजर जुगत किशोर कटेवा एवं अजय सिंह कटेवा ने सभी आधार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी उम्मेद सिंह महल्ला ने किया।

इस मौके पर जिला परिषद सदस्य बीरबल सिंह गोदारा, सुभाष लांबा, भाजपा नेता किशोर सिंह मिठारवाल, रामावतार महला, रघुवीर सिंह टॉक छीलरी, रामलाल सांखणिया, किसान नेता अशोक मिठारवाल, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष किशनलाल गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष बीरबल यादव, बाबूलाल कटेवा, बीरबल धेधरवाल, सांवरमल गिला, पूर्व सरपंच सतीश भीरकर, योगेंद्र सिंह शेखावत, धर्मवीर सिंह शेखावत, जीएसएस अध्यक्ष रामनिवास, रणवीरसिंह, बीरबल सिंह, ताराचंद, चौकलराम, सुल्तान राम थोरी, सहित कई लोग मौजूद रहे।

मिस्त्री द्वारा आत्महत्या का मामला : पुलिस को सुसाइड नोट मिला

सुसाइड नोट में आवास योजना अंतर्गत लोन लेने तथा किस्त भरने जैसी बातों का जिक्र

सादुलपुर, (निर्स)। राजगढ़ कस्बे में घर गेज एक 35 वर्षीय बाइक मिस्त्री द्वारा अपनी ही दुकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक के कपड़ों से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सुसाइड नोट में आवास योजना अंतर्गत लोन लेने तथा किस्त भरने जैसी बातों का जिक्र करते हुए एक संदीप मिस्त्री नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि संदीप ने उसके खिलाफ काफी रूप्य बना रखे हैं और ब्लैकमेल कर रहा है। हालांकि मृतक के भाई राकेश कुमार पुत्र सरंग लाल नाई ने दर्ज मामले में सुसाइड नोट का जिक्र नहीं किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मृतक नरेश कुमार

ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं नरेश कुमार बहुत परेशान हूँ। मैं मेरी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ। मेरे पर कोई कर्जा नहीं है। और ना ही मेरे ऊपर कोई दबाव है। मैंने ऑनलाइन लोन ले रखा है। जिसकी किस्त भर रखी है और मेरा आवास योजना का लोन भी चल रहा है, हो सके तो माफ कर देना, मैं सब से सारी बोलना चाहता हूँ अगर कोई मेरे घर वालों को परेशान करता है या मेरे भाई या मेरी बहन को या मेरी वाइफ को परेशान करता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है और कोई गरीब आदमी ना मेरे संदीप मिस्त्री ने मेरे खिलाफ काफी रूप्य बना रखे हैं और मुझे ब्लैकमेल

कर रहा है। गौरतलब है कि मामले में राकेश कुमार पुत्र शंकर लाल नाई ने मामले दर्ज करवाकर बताया था कि उसका छोटा भाई नरेश कुमार जो गीता देवी स्कूल के पीछे मोटरसाइकिल सर्विस की दुकान कर रखी है। उसका छोटा भाई हमेशा शाम को 7-8 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन 24 मार्च को शाम को दुकान से घर नहीं पहुंचा तो शहर में हर संभावित जगहों पर तलाश किया पृथक्ताछ भी की, लेकिन कोई पता नहीं चला। 25 मार्च को ललाभाग आरंभ भाई की दुकान को खोल कर देखा तो दुकान में पंखे के हुक से रस्सी का फंदा बनाकर फांसी पर लटका हुआ मिला तथा उसके भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

कोषाधिकारी कार्यालय को कुर्क करने के आदेश जारी

जालोर, (कासं)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जालोर प्रिया टवरी ने कोषाधिकारी कार्यालय की ओर से पेंशनर के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं करने पर कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिये हैं।

सीजेएम जालोर के समक्ष पेंशनर मुजपर हुसैन ने दावा प्रस्तुत किया कि वह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त है तथा

उसे मेडिकल के बिलों व इलाज का भुगतान पेंशनर होने से कोष कार्यालय द्वारा किया जाता है। करीब एक लाख रुपये अधिक रुपये के मेडिकल बिलों का भुगतान कोष कार्यालय द्वारा नहीं करने पर वसूल का दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने कोष कार्यालय को पेंशनर के मेडिकल बिलों की राशि का भुगतान करने का आदेश

दिया। आदेश के बावजूद भुगतान करने पर इजराय प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कोषाधिकारी कार्यालय को कुर्क करने के आदेश जारी किये, जिसके बाद कोर्ट के सेल आमीन ने बुधवार को कोषाधिकारी को कुर्क के आदेश से अलग करवाया। इसके बाद कोषाधिकारी ने दो दिन का समय मांगा है।

पारंपरिक जांच प्रणाली अपराधियों पर शिकंजा कसने में प्रभावी: एडीजी घुमरिया

आईओसीएल पाइप लाइन में लिकेज से हड़कंप मचा

पानी चोरी करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया

कोतवाली थाना और सीईओ ग्रामीण कार्यालय का एडीजी हवासिंह घुमरिया ने निरीक्षण किया

अजमेर, (कासं)। पुलिस की पारंपरिक जांच प्रणाली अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज भी प्रभावशाली है। यह शब्द अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवासिंह घुमरिया ने बुधवार को कोतवाली थाना और सीईओ ग्रामीण कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान कहा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया तथा रिपोर्टों की जांचकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली और अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।

एडीजी हवासिंह घुमरिया ने निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पुलिस में नवाचार इन्ोवेशन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन पारंपरिक जांच प्रणाली आज भी अपराधों को कम करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने में बेहद प्रभावी साबित होती है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक जांच प्रक्रिया में अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचने और अपराध पर नियंत्रण पाने

■ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवासिंह घुमरिया ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिर्देश

की अधिक संभावनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक का युग है और हर दिन नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। पुलिस विभाग नई तकनीकों को स्वीकार करता है और अपने सिस्टम में शामिल कर रहा है, जिससे अपराध जांच की प्रक्रिया को अधिक सटीक और प्रभावी बनाया जा सके, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की पारंपरिक जांच प्रणाली आज भी अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने में ज्यादा कारगर होती है।

थाने का किया निरीक्षण

रिपोर्टों की जांच की :-निरीक्षण के दौरान एडीजी घुमरिया ने पुलिस रिपोर्टों को बारीकी से जांच की और पुलिस स्टफ से विभिन्न विषयों पर सवाल-जवाब किए। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा की और अपराधों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने यह भी देखा कि थाने में आने वाले आमजन की शिकायतों का निस्तारण किस तरह किया जा रहा है और पुलिस उनकी कितनी सुनवाई कर रही है।

निरीक्षण के दौरान एडीजी ने पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पुलिस थानों में शिकायतों के त्वरित निस्तारण जनता के प्रति संवेदनशीलता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

मालपुरा, (निर्स)। पचेवर थाना क्षेत्र से होकर गुजर रही आईओसीएल पाइप लाइन में बुधवार की दोपहर मलिकपुर के पास लाइन में आग लगने की सूचना से हड़कम्प मच गया।

आग की सूचना पर पाइप लाइन कम्पनी के अधिकारी सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। चिकित्सा विभाग की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। सभी अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर पाइप लाइन में आग लगने व बड़ा हादसा घटित होने से पूर्व रोकथाम को लेकर मॉकड्रिल की जानकारी सामने आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। इंडियन ऑयल की और से महाप्रबंधक चाकसू बेस ले. कर्नल सोनी ने बताया कि समय-समय पर कम्पनी द्वारा आपातकालीन स्थितियों से निपटने तथा आमजन को जागरूक

■ मॉकड्रिल की जानकारी सामने आने के बाद राहत मिली

करने के उद्देश्य से मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। मॉकड्रिल में प्रशासनिक अधिकारी व कम्पनी अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सा विभाग की टीम एवं एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने की तत्परता का भी पूर्वाभ्यास किया जाता है। बुधवार को मलिकपुर के पास यह मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल के दौरान डीवाईएसपी आशीष प्रजापत, पचेवर थाना पुलिस टीम, आईओसीएल कम्पनी से महेन्द्र कुमार मीणा, नेराम मीणा, हितेश मीणा, वीरसिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे।

चलते ट्रैलर में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई

अवैध बजरी से भरे पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

पाली, (निर्स)। पाली में सोलर प्लेट्स से भरे एक ट्रैलर में चलते हुए बीच रास्ते अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ऐसे में ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब तक लाखों रुपए की सोलर प्लेट्स जल चुकी थी। हादसा बुधवार सुबह करीब पाँच बजे हाइवे पर जाड़न के पास हुआ।

ब्यावर जिले के राजेंद्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह ने बताया कि वह सोमवार शाम को किशनगढ़ से सोलर प्लेट्स भरकर कर गुजराने के लिए निकला था। रास्ते में गाड़ी खराब होने पर उसे दुरुस्त करवाया। बुधवार सुबह जाड़न से आगे निकला ही था कि हाइवे पर शर्मा पेट्रोल पम्प के सामने अचानक ट्रैलर के पिछले हिस्से में आग लग गई। इस पर उसे बुझाने का प्रयास किया लेकिन कामयाब

नहीं हो सका। ऐसे में पुलिस और दमकलकर्मियों को सूचना दी। हादसे की सूचना पर जाड़न, पाली, सोजत से तीन दमकलों के साथ दमकलकर्मियों मौके पर पहुंचे। दमकलों ने कई घंटे करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर और उसमें रखी सोलर प्लेट्स जल चुकी थी। हादसे के चलते यातायात भी बाधित रहा।

निर्वाह, (निर्स)। बरोनी थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने तीन अलग-अलग स्थानों से अवैध बजरी से भरे हुए पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं। थानाधिकारी बृजेंद्रसिंह ने बताया कि पुलिस की टीम ने पहाड़ी कट, दीक्षा पेट्रोल पंप कट व नला रोड से अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है।

मालपुरा संवाददाता के अनुसार

पचेवर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुये बुधवार को एक ट्रैक्टर को अवैध बजरी परिवहन करते जल कर चालक गजेन्द्र शाह निवासी विधानगर जिला ब्यावर की गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में अवैध बजरी परिवहन करते टोडारयसिंह थाना पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर फसे हुए चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया।

शाहपुरा जिला बहाली की मांग को लेकर 85वें दिन भी धरना जारी

जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में 28 मार्च को शाहपुरा के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे



शाहपुरा जिले की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया।

शाहपुरा, (निर्स)। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में 85 वें दिन बुधवार को वार्ड नंबर 17 के वार्डवासियों ने प्रॉपर्टी संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा व एडवोकेट शरीफ मोहम्मद के नेतृत्व में क्रमिक अनशन पर बैठकर नारेबाजी की एवं उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

रेडीमेड, मोबाइल, सर्राफा, चाय की थड़ी, फूट व सब्जी मंडी आदि संगठनों से पूर्व की भांति 28 मार्च को अपने व्यवसाय पूरे दिन बंद रखकर सहयोग करने की अपील की। 28 मार्च को सभी व्यवसायिक संगठन स्वीच्छिक रूप से अपने व्यवसाय बंद रखकर महलों के चौक से विशाल रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। 28 मार्च को जिला बचाओ संघर्ष समिति शाहपुरा का प्रतिनिधिमंडल भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री से मिलकर जिले बहाली की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा संघर्ष समिति द्वारा तय की जाएगी। मंच

संचालन अविनाश शर्मा ने किया। इस मौके पर एडवोकेट आशीष पालीवाल, गजेन्द्रप्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह भाटी, एडवोकेट ताज मोहम्मद, कुलदीप यादव तथा संघर्ष समिति के सदस्य सूर्य प्रकाश ओझा, उदय लाल बैरवा, हाजी उस्मान खिषा, सत्यनारायण पाठक, धनराज जीनगर, नंदलाल मिस्त्री, रोशन बिसायती, इनायतुल्लाह मंसूरी, दीपक शर्मा, आजाद रंजरेज, अब्दुल हमीद लोहार, अरूण राव, पंकज पाराशर, अकील पटान, ताज पटान, पार्शद अमजद खान, बरकत कायमखानी, अमीरदीन पटान, आरिफ रंजरेज मिस्त्री उपस्थित रहे।

पाली, (निर्स)। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में 22 साल की विवाहिता पायल की उपचार के दौरान मौत के मामले में परिजनों ने उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और शव के पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं हुए। मामले में बुधवार को एक डॉक्टर को निलंबित किया गया है। जांच कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले की जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट देगी। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने भी देर रात को मामला दर्ज किया। इस पर परिजन बुधवार दोपहर को शव के पोस्टमॉर्टम के लिए राजी हुए। वहीं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया।

जानकारी के अनुसार पाली के मिलगेट क्षेत्र में रहने वाली 22 साल की पायल पत्नी नवीन कुमार को बुखार, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत पर परिजनों ने 25 मार्च मंगलवार सुबह डॉक्टर को चेक करवाया गया और उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। ऐसे में उसे आईसीयू में भर्ती किया। जहां मंगलवार शाम करीब सात बजे उन्हें बताया गया कि पायल की मौत हो गई है। परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन परिजन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर



चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने हंगामा किया।

अड़े रहे और आईसीयूवार्ड के बाहर धरने पर बैठ गये। मामले में मंगलवार देर रात को पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के आशवासन के बाद और मृतका के परिजनों की रिपोर्ट दर्ज होने पर परिजन शव मोर्चरी में रखवाने को राजी हुए।

मामले में मृतका को पीएच, ससुराल और समाज के लोग बुधवार सुबह से ही मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में पहुंच गए। हंगामे की आशंका के चलते भारी पुलिस जापा भी तैनात रहा, लेकिन परिजन पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ

कार्रवाई करने की मांग की। आखिरकार , तहसीलदार जितेंद्र बरेबरवाल, डॉ. विकास मारवाल, बांगड़ हॉस्पिटल के डॉ. चौधरी सहित अन्य ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की और प्रारंभिक जांच के बाद डॉ. सूर्यवीर को निलंबित करने का आदेश जारी किया। वहीं डॉ गौरव कटारिया, डॉ प्रवीण गर्ग के नेतृत्व में गठित टीम को पूरे मामले की जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात कही। इस सारी कार्रवाई से मृतका के परिजनों को अलग करवाया गया। तब जाकर वे बुधवार दोपहर करीब

- मामले में एक डॉक्टर को निलंबित किया और जांच कमेटी गठित की
- परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, पोस्टमॉर्टम को राजी हुए परिजन

डॉक्टरों की लापरवाही से गई हमारी बहन की जान मामले में मृतका पायल के भाई निर्मल वेद्य, रामचंद्र ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी बहन की अकाल मौत हुई है। वह तो बिलकुल ठीक थी। कुछ महीने पहले ही उसने प्रियांश को जन्म दिया था। डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया जो उसकी मौत का कारण बना। लेकिन अब क्या हो सकता है हमारी बहन तो वापस लीट कर नहीं आ सकती। इतना कहते हैं दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगे।

मामले में बांगड़ हॉस्पिटल के डॉ. एचएम चौधरी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर सूर्यवीर को निलंबित किया है। मेडिकल बोर्ड से मृतका की बाँटी का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है।

किसान सम्मेलन : धरती पुत्रों का बढ़ाया मान

उदयपुर, । राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित हो रहे साप्ताहिक महोत्सव के तहत दूसरे दिन बुधवार को किसान सम्मेलन हुआ।

■ खातों में आया अनुदान

विभाग सेवा करने वाला विभाग है, हमारे किसान भाई अधिक से अधिक विभागीय योजनाओं का लाभ लें। समाजसेवी गजपाल सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से कृषक वर्ग का कल्याण हो रहा है। समाजसेवी प्रमोद सागर ने कहा कि देश में जब-जब खाद्यान्न की समस्या आई किसान वर्ग ने ही देश को सम्भल देने का काम किया है। एफपीओ के माध्यम से किसानों के सपने पूरे होंगे, कृषकों हेतु सरकार ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। सम्मेलन में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कई किसानों को लाभान्वित किया।

इसमें बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया गया। साथ ही जिला स्तर पर भी धरती पुत्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरण किया। कार्यक्रम की संबोधित करते हुए उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मोणा ने कहा कि कृषि

उदयपुर में 26380 लाख रूपए व सलूम्वर में 9086 रूपए लाख के प्रस्ताव

■ जिला परिषद की विशेष साधारण सभा आयोजित

प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव के आदेशों की अनुपालना में विशेष साधारण सभा आयोजित की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के उदयपुर और सलूम्वर अधीक्षण अभियंताओं ने अपने-अपने क्षेत्र के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए उनका वाचन किया। उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 की आबादी तथा गैर जनजाति क्षेत्रों में 500 की

आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। उदयपुर जिले में कुल 346.30 किलोमीटर लंबाई की कुल 141 सड़कों के लिए 26380 लाख रूपए तथा सलूम्वर जिले में 129.5 किलोमीटर लंबाई की कुल 59 सड़कों के लिए 9086 लाख रूपए के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सदन ने इन प्रस्तावों का अनुमोदन किया। सदस्यों ने अवगत कराया कि कुछ गांव ऐसे भी हैं, जिनकी वर्तमान जनसंख्या योजना के मापदण्डों के अनुरूप है, लेकिन आधार वर्ष 2011 की जनगणना होने से प्रस्तावों में शामिल होने से वंचित रहे हैं। उन्होंने ऐसे गांवों के लोगों की आवागमन समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री श्री

खराड़ी से आग्रह किया। इस पर कैबिनेट मंत्री ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जिले में वन विभाग की अनारपित के इंतजार में अटक के सड़क निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई प्रकार के जिला स्तर पर सुलझाने योग्य हो सकते हैं। ऐसे मामलों को जिला कलक्टर से चर्चा कर निस्तारित कराएं, जो राज्य स्तर से निस्तारित होने हैं, उनके बारे में सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उनका समाधान कराया जा सके। बैठक में प्रधानाण, जिला परिषद सदस्यगण तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उदयपुर के पिम्स के डाक्टरों ने महिला की जान बचाई

■ पिम्स में डॉक्टरों ने 'भूत-प्रेत का साया' समझी गई महिला की जान बचाई

उदयपुर, । पेंसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स हॉस्पिटल, उमरखा में चिकित्सकों ने भूत-प्रेत का साया समझी गई महिला की जान बचाई है। पिम्स के चैयरमेन आशीष अग्रवाल ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के लोहारगढ़ की 32 वर्षीय गृहिणी को 13 मार्च को होली से एक दिन पहले पिम्स हॉस्पिटल, उमरखा के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया। जब मरीज को लाया गया, तो उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। परिवार के अनुसार पिछले 5 दिनों से उनका व्यवहार अजीब था, जैसे उन पर किसी आत्मा का साया हो। परिजनों ने बताया कि वह खाना नहीं खा रही थीं, सो नहीं रही थीं और मरे हुए रिश्तेदारों के बारे में चिन्ता रही थीं। उनकी आवाज भी बदल गई व बहुत तेज व भारी हो गई थी। कभी-कभी वह आसपास के लोगों को जबरदस्ती पकड़

लेती थीं। डर के कारण परिवार उन्हें पहले भोपों और तांत्रिकों के पास ले गया, जिन्होंने कहा कि उन पर भूत-प्रेत का साया है और वह नहीं बचेंगी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जब डॉक्टरों ने मरीज को आईसीयू में भर्ती करने को कहा तो उसके पति ने डरते हुए कहा कि अगर आप जान बचाने की गारंटी देते हैं, तभी हम भर्ती करेंगे लेकिन डॉक्टरों ने परिवार का विश्वास जीतकर उन्हें अस्पताल में एक हफ्ते तक रखने के लिए राजी कर लिया। डॉक्टरों ने उन्हें 24 घंटे तक बेहोशी की दवा देकर शांत किया।

बदलते परिवेश में महिलाओं के प्रति पुरुष प्रधान समाज को सोच बदलनी होगी : डॉ मंजू

■ महिला अधिवक्ताओं का सम्मान किया

उदयपुर, । महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकाृता मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि बदलते परिवेश में और सम्मान में बदलती धारणाओं के बीच महिलाओं को सम्मान एवं सम्मानता देनी होगी और पुरुष प्रधान समाज को महिलाओं के प्रति सोच बदलनी पड़ेगी।

समाज में अच्छा मैसैज जा रहा है। बार एसोसिएशन उदयपुर एवं अधिवक्ता परिषद उदयपुर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में बार सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में "बेटी राह का सम्मान" संगोष्ठी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि डॉ. मंजू बाघमार महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकाृता मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर एवं अध्यक्षता वाणिज्यिक न्यायालय न्यायाधीश महेन्द्र कुमार दवे तथा विशिष्ट अतिथि

डॉ मंजू बाघमार बुधवार को उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बेटी राष्ट्र का सम्मान संगोष्ठी को संबोधित कर रही विभाग अधिकाृता मंत्री राजस्थान थीं। डॉ मंजू ने कहा कि आज कल न्यायालय द्वारा बच्चियों एवं महिलाओं को सुरत न्याय दिया जा रहा जिससे

अपर जिला न्यायाधीश दमियन्ती पुरोहित एवं अधिवक्ता परिषद की प्रान्त उपाध्यक्ष वन्दना उदावत में। प्रारम्भ में अधिवक्ता परिषद के जिला संयोजक मनीष शर्मा ने स्वागत संगोष्ठी के आयोजन पर प्रकाश डाला। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्रभान सिंह ने कहा कि महिला शक्ति पूर्व में भी सशक्त थी, आज भी है और आगे भी होगी। वाणिज्यिक न्यायालय न्यायाधीश महेन्द्र कुमार दवे ने कहा कि बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के कुछ अन्दर कुछ कानूनों में बदलाव की जरूरत है।

कार्यशाला का शुभारम्भ

उदयपुर, । माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं टीआरआई, उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में "जनजाति भित्ति चित्रण एवं माण्डना कला" पर चार दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम के निदेशक ओ. पी. जैन ने कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बताया कि आदिवासी अंचल के कलाकारों की प्रतिभा को दुनिया के समक्ष लाने व उनके तैयार कलाकृतियों की मार्केट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्यशाला रखी गयी है। कार्यशाला के

मुख्य अतिथि एमएलएसयू के सामाजिक विज्ञान व मानविकी कॉलेज के डीन मदन सिंह राठौड़ ने महिला कलाकारों को कला की आत्मा बताते हुए आदि एवं आदि कला पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि मीरा गर्लस कॉलेज के सह आचार्य रामसिंह भाटी ने कहा कि माण्डना भूमि पर विशिष्ट अवसरों पर बनाये जाते हैं जबकि भित्ति चित्र द्वारा कलाकार अपने भावों की अभिव्यक्ति दीवार पर उकेर कर देता है। अब वे यहां कार्यशाला में केनवास पर अपनी प्रतिभा को उकेरेंगे। कार्यशाला में विभिन्न जिलों के 24 कलाकार केनवास पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

टावर लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, । झाड़ोल थाना पुलिस ने मोबाईल टावर लगाने पर लाखों का लाभ मिलने का झांसा देकर पीठों से नकदी हड़पने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण के अनुसार कोचला झाड़ोल निवासी मेरुलाल पुत्र धर्मा ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 11 मार्च 25 को दोपहर में जगदीश यादव पुत्र श्रीलाल निवासी आमौर कला मूराना मध्यप्रदेश भरे घर आया। जहां उसने स्वयं को वीआईएफ टावर कंपनी सेप्टल दिल्ली का सुपरवाइजर अधिकारी होना बताया।

बातचीत के दौरान उसने जमीन पर टावर लगाने की बात कही तथा सहमती देने पर नौकरी प्रतिमाह 12 हजार रुपये, 8 हजार रुपये किया, 22 लाख रुपये जमीन का मुआवजा मिलने की बात कही साथ ही 1 लाख रुपये देने पर 6 लाख रुपये मुआवजा बढ़ कर 28 लाख करने का आश्वासन दिया। इसके लिए उसने 8 हजार रुपये मांगे तो मैंने 6600 रुपये दिये। उसके बाद से आज दिन तक कोई टावर नहीं लगा। इसी तरह भरे मित्र देवीलाल पुत्र नाथू निवासी लुणावतों का खेवाड़ा के साथ भी टावर लगाने के नाम पर 4 हजार

रुपये की धोखाधड़ी को इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के साथ भी धोखाधड़ी करने की जानकारी सामने आई। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उपाधीक्षक नेत्रपालसिंह के सुपरविजन में झाड़ोल थानाधिकारी फैलीराम मोणा के नेतृत्व में गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जगदीश पुत्र श्रीलाल निवासी आमौर कला मूराना एमपी को उदयपुर में स्थित होटल से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा लोक-सूचना दिनांक: 26/03/2025			
जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथद्वारा	4085/2867, 4066/2867, 4345/4018, 4341/3995	कुल किता 04रकबा 0.6159 हैक्टेयर

कार्यालय नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ जिला उदयपुर (राज.) दिनांक: 24/03/2025			
:-: लोक-सूचना :-:			
जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
मावली, उदयपुर	राजव ग्राम -वासनीमाफी पटवार हल्का-फतहनगर	11299/615	रकबा 0.1227 हैक्टेयर यानि 13202.52 वर्ग फीट यानि 1466.94 वर्गचौगुल 1227वर्गमीटर

कार्यालय नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ जिला उदयपुर (राज.) दिनांक: 24/03/2025			
:-: लोक-सूचना :-:			
जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
मावली, उदयपुर	राजव ग्राम -वासनीमाफी पटवार हल्का-फतहनगर	1296/709	रकबा 0.0645 हैक्टेयर यानि 6940.20 वर्ग फीट यानि 771.13 वर्गचौगुल 645 वर्गमीटर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द सं. 9852-53 दिनांक: 26/03/2025				
क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	गुडली	213 547/223 605/225	रकबा 0.2023 हैक्टेयर रकबा 0.0647 हैक्टेयर रकबा 0.3348 हैक्टेयर

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.) दिनांक: 24/03/2025						
:-:आपत्ती सूचना:-						
क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पुर्व	परिचय	उत्तर	वर्ष
1	श्रीमती अनुष्ठा धारवी पत्नी श्री जगदीश धारवी होली मंगरा, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या 16 क्षेत्रफल 2184.50 वर्गफिट, नाथद्वार	भूखण्ड संख्या 17	आम रास्ता 30 फिट चौड़ा	अन्य भूमि चौड़ा	आम रास्ता 30 फिट चौड़ा

प्रतिभागी सीखेंगे रंगमंच छायांकन की बारीकियां

उदयपुर, । पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से विश्व रंगमंच दिवस (के उपलक्ष्य में दो दिवसीय थिएटर फोटोग्राफी कार्यशाला का शुभारंभ गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्य अतिथि श्रद्धा मुर्डिया करेंगी। इस दौरान आमजन सहित समस्त प्रतिभागी राजदीप द्वारा खींचे गए 50 चुनिंदा रंगमंचों छायाचित्रों की प्रदर्शनी भी देख सकेंगे। केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि कार्यशाला 27 मार्च को शिल्पग्राम स्थित दर्पण सभागार में होगी। पहले सत्र में थिएटर फोटोग्राफी के उपकरणों व लाइटिंग पर चर्चा होगी। वहीं, दूसरे सत्र में प्रतिभागी व्यावहारिक अभ्यास करेंगे तथा सांध्यकालीन सत्र में मंचित नाटक की फोटोग्राफी करेंगे। कार्यशाला में वरिष्ठ छायाकार राकेश शर्मा 'राजदीप' प्रतिभागियों को रंगमंचीय छायांकन की बारीकियां सिखाएंगे। इसमें प्रतिभागी मोबाइल और डीएसएलआर कैमरा दोनों ही तकनीक से बेहतरीन फोटो/वीडियो के टिप्स सीख सकेंगे।

फैक्ट्री से ऑयल ड्रम चोरी

उदयपुर, । शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने फैक्ट्री कर्मचारियों के खिलाफ ऑयल ड्रम चुरा ले जाने का मामला दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित अंकित कुमार पुत्र सुशील कुमार सोनी निवासी उदय विहार मादड़ी हॉल प्रतापनगर ने कर्मचारी निरिन पुत्र प्रमोद तथा गौतमलाल पुत्र भूरालाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने मादड़ी रोड़ नंबर 12 पर स्थित एमआईए फैक्ट्री में काम करते हुए वहां से ऑयल से भरे 7 ड्रम चुरा ले गए। इसका पता स्टॉक मिलान पर चला। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

बस और कार की भिड़ंत में दो की मौत

उदयपुर,।सलूम्वर जिले के जावरमाइन्स थाना क्षेत्र पलुना मेधा हाइवे पर पर बस ने कार को चपेट में ले लिया। हादसे में दो जनों की मौत हो गई तथा तीन जने घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को सराड़ा से सलूम्वर रूट पर जाने वाली बस जयसमन्द के समीप पलुना रोड़ पर सराड़ा रूट पर चलने वाली बस ने कार को चपेट में ले लिया। हादसे में ओवेश पुत्र अशरफ रजा निवासी बिच्छुघाटी, सैय्यद नसीम पुत्र सैय्यद फरीद निवासी अम्बामाता, हुसैन बानो पत्नी अशरफ रजा निवासी बिच्छुघाटी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि शाहबाज पिता सिद्दिकी निवासी, नजमा बानो पति शरीफ मोहम्मद निवासी सवीना, नसीम बानो पत्नी दिलदार गंभीर रूप से घायल हो गये। कार से उदयपुर से सलूम्वर की तरफ जा रही थी एवं यात्रियों से भरी निजी बसी सलूम्वर आ रही है। पलुना मेधा हाइवे पर बस ने कार को चपेट में ले लिया।



पहले से कंपोजिशन योजना का लाभ उठा रहे पात्र करदाताओं को फॉर्म GST CMP-02 दाखिल करना आवश्यक नहीं है

पत्र करदाता, जो कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर निम्न प्रक्रिया द्वारा कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं:

- करदाता इंटरफेस पर लॉगिन करें
- 'Services > Registration > Application to Opt for Composition Levy' पर जाएं
- फॉर्म GST CMP-02 भर कर जमा करें

आसान और सुविधाजनक अनुपालन

आकर्षक कर दरें

न्यूनतम अनुपालन आवश्यकताएं

स्वतः नवीकरण और योजना को छोड़ना भी सरल

माल एवं सेवाओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए उपलब्ध

कम बही खातों की आवश्यकता

पहले से कंपोजिशन योजना का लाभ उठा रहे पात्र करदाताओं को फॉर्म GST CMP-02 दाखिल करना आवश्यक नहीं है

* आपूर्तिकर्ताओं के प्रकार	# वित्त वर्ष 2024-25 में सकल वार्षिक टर्नओवर
माल के आपूर्तिकर्ता	08 विनिर्दिष्ट राज्यों में पंजीकृत करदाता ₹. 75 लाख तक
सेवाओं के आपूर्तिकर्ता	अन्य राज्यों में पंजीकृत करदाता ₹. 150 लाख तक
	₹. 50 लाख तक

अधिक जानकारी के लिए कृपया जीएसटी अधिनियम की धारा 10, सीजीएसटी नियम 3 से 7 और अधिसूचना सं. 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 07.03.2019, को देखें।

जीएसटी कंपोजिशन योजना: छोटे करदाताओं के लिए बड़े लाभ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

@cbicindia @cbic_india @cbicindia @cbicindia @CBIC India

इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में शरीर के अंगों को पकड़ने व कपड़े खींचने को अपराध नहीं माना था

नयी दिल्ली, 26 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादित आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना दुष्कर्म के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से कड़ी असहमति व्यक्त की और इसे 'चौकाने वाला' बताया।

न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, यह एक गंभीर मामला है। न्यायाधीश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की ओर से पूरी तरह असेवेदनशीलता बरती गई है। यह समान जारी करने के चरण में था। हमें न्यायाधीश के खिलाफ ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग करने के लिए खेद है।

■ **जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चौकाने वाला बताया और असहमति जताई।**

पीठ ने इन टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दिया और भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में शामिल पक्षों को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हालांकि शीर्ष न्यायालय को आमतौर पर इस चरण में रोक लगाने में हिचक है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गयी टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों के विपरीत थीं और एक अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती थीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर सहमति जताते हुए कि यह एक 'चौकाने वाला' फैसला था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मामले को लिया गया, वह बेहद गंभीर था। उन्होंने सुझाव दिया

कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रेस्टर के मास्टर के रूप में कदम उठाने चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता की ओर से एनजीओ 'जी द वूमन ऑफ इंडिया' का प्रतिनिधित्व करते हुए विवादास्पद फैसले को उजागर करते हुए एक पत्र लिखे जाने के बाद मामला शीर्ष न्यायालय पहुंचा। एक अन्य एनजीओ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' ने कहा कि वह भी मामले में पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, एनजीओ 'वी द वूमन ऑफ इंडिया' ने हमारे संज्ञान में लाया कि 17 मार्च, 2025 को पारित फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा

की गई कुछ टिप्पणियों से पता चलता है कि फैसले के लेखक में संवेदनशीलता की कमी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया, बल्कि करीब चार महीने तक इसे सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उचित विचार-विमर्श और दिमाग लगाने के बाद फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि चूंकि टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और पूरी तरह असेवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए टिप्पणियों पर रोक लगाना मजबूरी है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 मार्च-2025 को अपने आदेश में कहा था कि इस तरह के कृत्य प्रथम दृष्टया यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पोर्सको) के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध बनेंगे, जिसमें कम सजा का प्रावधान है।

कांग्रेस के 70 सांसद लोकसभाध्यक्ष बिड़ला से मिले

नयी दिल्ली, 26 मार्च। लोकसभा के कांग्रेस के उपनेता गौरव गोर्गोई के नेतृत्व में पार्टी के 70 सदस्यों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से उनके कक्ष में मुलाकात की और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। गोर्गोई के साथ इस दौरान कांग्रेस महासचिव तथा पार्टी के लोकसभा सदस्य के.सी. वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर सहित, पार्टी के 70 लोकसभा सदस्यों ने बिरला से मिलकर गांधी को बोलने नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए विरोध दर्ज किया।

पेपर लीक केस, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) परीक्षाओं के पेपर लीक करने लग गया। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के दौरान भी इन सभी ने पेपर लीक किया था, जिससे परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। राजेश कुमार यादव इस स्कूल में परीक्षा प्रभारी था और उसने स्टूडेंट्स रूम में यूनिक भाम्बू को प्रवेश करवाकर मोबाइल से पेपर की फोटो खिंचवाई थी। राजेश कुमार यादव ने पेपर लीक के जरिए एक बेटे को पी.डब्ल्यू.डी. में इंजीनियर बनवाया तथा बहू को महाराणी स्कूल में फस्ट ग्रेड टीचर बनवाया था।

अमेरिका से आयातित सामान पर भारत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो रही, अमेरिका ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी का जवाब है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल मचा दी है और कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी थी, जिसमें अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं। अमेरिकन नीति का साइड इफेक्ट कम करने के लिए भारत सक्रिय कदम उठा रहा है।

अमेरिका के अडिस्टैंट यूएस ट्रेड रिजनेटिवेटिव ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए भारत आया था। चर्चा में एक न्यायोचित प्रेमवर्क तैयार करने की बात की गई ताकि दोनों देशों में द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। यात्रा में बताया गया कि दोनों देश व्यापारिक विवाद हल करने व आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन वार्ता का आधार 2025 के अंत तक ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना था और आपसी व्यापार 200 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक करना था। टैरिफ कटौती और बाजार तक पहुंच, खासकर कृषि व औद्योगिक उत्पाद के क्षेत्र में, पर चर्चा की गई।

घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने व निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों व मोबाइल फोन बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय अमेरिकी

■ **फंडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि सरकार उनकी मदद करे, ताकि वे भारत में निर्मित सामान को अमेरिका में "डिस्प्ले" कर सकें। उदाहरण के लिये भारतीय बिजनेस के लिए, अमेरिका के ट्रेड-एक्सपो में भाग लेना आसान करे।**

टैरिफ का सामना कर रहे घरेलू उत्पादकों को मदद देने के लिए है। इसके अलावा भारत की एक संसदीय समिति ने सरकार को आयातित कच्चे माल पर टैरिफ घटाने का सुझाव दिया। इस सिफारिश का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को कर प्रणाली के बदलाव से राहत है, जहाँ कच्चे माल पर टैक्स तैयार उत्पाद से अधिक होता है और इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।

सरकारी विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिकन टैरिफ के नए प्रस्ताव से भारत से हो रहे अमेरिकी निर्यात का 87 प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। इस गिरावट को रोकने के लिए भारत 55 प्रतिशत अमेरिकन आयात से 5 से 30 प्रतिशत तक शुल्क कटौती कर सकता है और कई उत्पादों पर तो टैक्स में भारी कटौती हो सकती है और कुछ को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पर अभी चर्चा ही चल रही है। अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वैकल्पिक उपयोग पर भी चर्चा चल रही है जिसमें सैक्टर के आधार पर टैरिफ का समायोजन और विशिष्ट उत्पादों पर चयनात्मक कटौती शामिल है।

चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मसला कृषि है। दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग की बात स्वीकार करते हैं लेकिन हितों के बीच जो खाई है उसे पाटना कठिन हो रहा है। भारत के नीति निर्माताओं पर आयातित कच्चे माल पर टैरिफ कम करने का दबाव है।

भारत के व्यापार निकायो में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। फंडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, फुटवियर और बायोकेमिकल्स पर जोर दिया है। संगठन के महादेशिक अजय सहाय ने सरकार से मांग की है कि अमेरिकन व्यापार प्रदर्शनियों में भारतीयों की सक्रिय भागीदारी के लिए मदद देने की मांग की है।

भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकन टैरिफ चिंता का विषय है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्डिनल ने सरकार से अमेरिकन सामानों जैसे स्टील स्क्रैप, नहर, कॉस्टिंग्स और फॉर्जिंग पर टैक्स घटाने की मांग की है।

आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, क्या यह समय भारत-अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में नया मोड़ साबित होगा या प्रगति को अवरुद्ध कर देगा। जैसे-जैसे समय करीब आ रहा है, दोनों देशों को निर्णय लेना होगा कि समझौते का रास्ता चुने या आर्थिक टकराव का जोखिम उठाएं।

न्यायालय कुछ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ...न्याय में आस्था रखने वालों को न्याय मिलेगा। लेकिन जो लोग कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें कानून की सीमा के अंदर सबक सिखाया जायेगा। कोई भी बात ऐसी भाषा में ही समझाई जानी चाहिये, जिसे लोग समझते हों। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास हिंसक वृत्ति के साथ आता है, तो क्या हम निकम्मे बने खड़े रहें?"

'किसान सिर्फ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इसीलिए हम किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसान उत्पादन संगठन मार्गदर्शिका का विमोचन किया तथा लाभार्थियों से संबद्ध किया। इस दौरान, सफल एफपीओ पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी. आर. चौधरी, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचन्द सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, जेठानंद व्यास सहित बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जिला पुलिस और लाइन का जाब्ता जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा तथा जेल विभाग को सूचना देकर सर्व शुरु कर दी।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विकासशील देशों के सार्वजनिक कर्ज प्रोफाइल पर नजर डालते हैं तो हम उभरते बाजारों और विकसित देशों के कर्ज प्रोफाइल में विशाल अंतर देखते हैं। ओ.ई.सी.डी. देशों में जारी किए गए संप्रभु कर्ज का 2025 में 17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 में 14 ट्रिलियन डॉलर था। उभरते बाजारों और विकासशील देशों का कर्ज आंकड़ा भी काफी बढ़ा है, लेकिन यह अमीर देशों के मुकाबले काफी कम है, जो 2007 में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर था और 2024 में 3 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है।

सरकारी कर्ज का एक पहलू, जो सामान्यतः कम सराहा जाता है, यह है कि सरकारी कर्ज को भुगतान के माध्यम से शायद ही कभी समाप्त किया जाता है। यह बस रीसाइकिल होते रहते हैं,

अर्थात् मैच्योर हो चुके पुराने कर्ज को नए कर्ज से चुकाया जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पुराने कर्ज को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। यदि ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, तो नए कर्ज उच्च ब्याज दरों पर लिए जाएंगे और इस प्रकार उधारी की कुल लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा।

वैश्विक वित्तीय बाजार वर्तमान में ट्रंप के हंगामों के कारण हचलच में हैं। व्यापार और आर्थिक नीतियों को लेकर अमेरिका की नीतियों में होने वाले बदलाव उलझन पैदा कर रहे हैं। शेरर बाजारों में व्यापक उतार-चढ़ाव हो रहा है और निवेशकों का पैसा स्टॉक्स से बॉण्ड्स की ओर जा रहा है। अमेरिका के लिए आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की जा रही है और खुद ट्रंप ने भी ऐसी संभावना को स्वीकार किया है। मंदी की कोई भी बात और

निवेशकों का पैसा स्टॉक्स से बॉण्ड्स में जाने के कारण ब्याज दरों में गिरावट होती है। अफवाहें फैल रही हैं कि अमेरिका को 17 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज मैच्योर होने वाले हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं है। आने वाले दिनों में ब्याज दरों में मामूली कमी अमेरिकी संघीय सरकार को अपने विशाल बकाया कर्ज को रीसाइकिल करने की ब्याज लागत को बचाने में मदद कर सकती है। इसलिए, ट्रंप के हंगामे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके थे, ताकि कर्ज रीसाइकिलिंग पर ब्याज का बोझ कम किया जा सके।

वैसे भी, जो भी हो, दुनिया कर्ज पुनर्संरचना के एक विशाल कार्य का सामना कर रही है। ओ.ई.सी.डी. रिपोर्ट में कहा है कि "आगे देखते हुए, कुल संप्रभु कर्ज का 42 प्रतिशत और सभी बकाया कॉर्पोरेट बॉण्ड कर्ज का 38 प्रतिशत अगले तीन वर्षों में मैच्योर होने

वाला है।"

रिपोर्ट यह भी बताती है कि ओ.ई.सी.डी. देशों के लिए रीफायर्नस लागत 2024 में जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत बढ़ गई है, जिससे कुल कर्ज भुगतान से जी.डी.पी. का अनुपात 3.3 प्रतिशत से अधिक हो गया है। यह कम से कम एक प्रतिशत अधिक है, जितना वे रक्षा पर खर्च करते हैं। अमेरिका के नए रणनीतिक रुख को देखते हुए, इन देशों के लिए इस प्रवृत्ति को पलटना अनिवार्य होगा।

सरकारी बॉण्ड्स के खरीददारों के प्रोफाइल में कुछ बदलाव दिख रहा है, जिसमें घरेलू स्रोतों से विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य की ओर जाना कर्ज भुगतान समस्याओं के स्थायी जोखिम को बढ़ा रहा है।

ओ.ई.सी.डी. रिपोर्ट के अनुसार, ओ.ई.सी.डी. देशों में, केन्द्रीय बैंकों द्वारा घरेलू संप्रभु बॉण्ड्स का स्वामित्व

2021 में कुल बकाया कर्ज का 29 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर 19 प्रतिशत हो गया, जबकि घरेलू परिवारों का हिस्सा 5 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत और विदेशी निवेशकों का हिस्सा 29 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है।

आइए, हम भारत के कर्ज प्रोफाइल और बाहरी झटकों के प्रति हमारी संवेदनशीलता पर एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था पर किया गया नवीनतम "आर्टिकल 4 कन्सल्टेन्स" से संबंधित कुछ पहलुओं की जानकारी मिलती है।

बाहरी कर्ज का जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में हिस्सा 18.9 प्रतिशत है और यह 2025-26 में घटकर 18.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसमें से शॉर्ट टर्म कर्ज केवल 8.3 प्रतिशत है, जिसे संवेदनशीलता का एक

मानक माना जाता है, क्योंकि यह तत्काल भुगतान के बोझ को दर्शाता है। कुल मिलाकर, कर्ज प्रोफाइल समय के साथ सुधर रहा है, क्योंकि फिस्कल कन्सॉलिडेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है और गवर्नमेंट फायर्नसेज में संतुलन प्राप्त किया जा रहा है। निस्संदेह, अर्थव्यवस्था की स्थिति में उत्साह, जिसका संकेत बढ़ते कर संग्रह से मिलता है, ने इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद की है। आखिरकार, बढ़ती लहर सभी नावों को ऊपर उठाती है, सरकार को भी और व्यक्ति को भी।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के स्वीकृत पदों की संख्या 50 है। ऐसे में स्वीकृत पदों के मुकाबले अभी भी न्यायाधीशों के 12 पद खाली हैं।

MARUTI SUZUKI ARENA

शानदार एरीना महीने में अविश्वसनीय ऑफर्स।

जल्दी कीजिए, ऑफर्स 31 मार्च तक।

5

DAYS LEFT

BUY BEFORE PRICE HIKE OF UP TO 4%

ऑफर्स स्टॉक रहने तक मान्य

3 years

100 000 km WARRANTY**

विशेष ऑफर

ALTO K10 ₹83 100* | SWIFT ₹58 100* | WAGONR ₹73 100*

SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at 1800-102-1800

T&C Apply Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. Offer valid with selected financiers only. All outlets are open on Sundays. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Above offers are valid till 31st March, 2025.